



RNI No. MAHBIL/2009/31730

Reg. No. MH/MR/South-329/2013-15

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ६, अंक १]

मंगळवार, मार्च २५, २०१४/चैत्र ४, शके १९३६

[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक १३

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

वित्त विभाग

मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांकित ३ मार्च २०१४ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. VII OF 2014.

AN ORDINANCE

FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX
ACT, 2002.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक ७ सन् २०१४।

महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके सन् २००५ कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकतर संशोधन का ९। करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खंड (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं ; अर्थात् :-

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, २०१४ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

संक्षिप्त नाम और
प्रारम्भण ।

सन् २००५ का
महा. ९ की धारा
२३ में संशोधन ।

२. महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ की धारा २३ की उप-धारा (१२) के पश्चात्, निम्न उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात् :—

सन् २००५
का महा.
९।

“ (१३) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी व्यौहारी के मामले में जो, फ्लैटों, निवासों या भवनों या परिसरों का संनिर्माण कार्य करता है और किसी करार के अनुसार भूमि के साथ या भूमि के रेखांकन हित में उनका अन्तरण करता है और जिसके मामले में किसी अवधि के लिये निर्धारण आदेश करने की सीमा ३१ मार्च २०१४ को समाप्त होती है तब, ऐसी अवधि के लिये निर्धारण आदेश ३० सितम्बर, २०१५ को या के पूर्व किया जा सकेगा । ” ।

वक्तव्य ।

वित्त विभाग की सरकारी अधिसूचना क्रमांक मूल्यवर्धित कर १५१३/सीआर-१४७/कराधान-१, दिनांकित २९ जनवरी २०१४ द्वारा महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर नियम, २००५ के नियम ५८ में संशोधन करने की दृष्टि से सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने भारत के निर्माणकर्ता संगम बनाम महाराष्ट्र राज्य (अपील करने की विशेष इजाजत (सिविल) क्रमांक १४१५३/२०१३) दिनांकित ३१ जनवरी, २०१४ के आदेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि, यदि इस आदेश और/या अधिसूचना दिनांक २९ जनवरी २०१४ के निबन्ध में पुनरीक्षित विवरणीयाँ प्रस्तुत करनेवाला याचिकाकर्ता ऐसी विवरणीयाँ, विधि के अनुसार समुचित संबंधित निर्धारण अधिकारी द्वारा परीक्षित करेगा ।

२. ब्यौहारियों के कतिपय निर्धारण के संबंध में सीमा अवधि जो फ्लैटों, निवासों या भवनों या परिसरों के संनिर्माण का कार्य करता है और करार के अनुसार भूमि के साथ या भूमि रेखांकन हित में उनका अन्तरण ३१ मार्च २०१४ को समाप्त होती है । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, निर्धारण के लिये ब्यौहारियों साथ ही साथ निर्धारण प्राधिकारियों के ऐसे वर्ग को पर्याप्त समय देने के लिये, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ (सन् २००५ का महा. ९) की धारा २३ की जोड़ी गयी उप-धारा (१३) द्वारा ३० सितम्बर, २०१५ तक निर्धारण के लिये सीमा विस्तार करना इष्टकर समझा गया है ।

३. क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ में अधिकतर संशोधन करने के लिये, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुम्बई,
दिनांकित २ मार्च २०१४ ।

के. शंकरनारायणन्,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

सुधीर श्रीवास्तव,
शासन के अप्पर मुख्य सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद)
श्रीमती ललिता देठे,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य ।